

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-3

देहरादून, दिनांक: 06 जनवरी, 2015

विषय:- नाबार्ड पोषित आर0आई0डी0एफ0 फेज-14 से 19 में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष पुनर्आवंटन/समायोजन की अनुमति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-7767/19 बजट (ना0वि0पो0)/2014-15 दिनांक 26.12.2014 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या-22, लेखा शीर्षक-5054, (आयोजनागत) नाबार्ड पोषित आर0आई0डी0एफ0 फेज-14 से 19 में शासनादेश दिनांक 27.06.2014 एवं शासनादेश दिनांक 02.09.2014 द्वारा अवमुक्त कुल धनराशि ₹ 25000.00 लाख (र दो सौ पचास करोड़) के सापेक्ष पुनर्आवंटन/समायोजन की स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त के क्रम सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नाबार्ड वित्त पोषित आर0आई0डी0एफ0 फेज-14 से 19 के लिए उल्लिखित शासनादेशों द्वारा अवमुक्त धनराशि ₹ 25000.00 लाख (र दो सौ पचास करोड़) के सापेक्ष उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के अनुसार, निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन पुनर्आवंटन/समायोजन की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. पत्र संख्या-7767/19 बजट (ना0वि0पो0)/2014-15 दिनांक 26.12.2014 के अनुसार उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के अनुसार ही पुनर्आवंटन/समायोजन की कार्यवाही की जाय।
2. नाबार्ड पोषित आर0आई0डी0एफ0 योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में वर्तमान तक, कार्यवार/फेजवार अवमुक्त की गयी धनराशि ₹ 25000.00 लाख (र दो सौ पचास करोड़) की सीमा तक ही संशोधित आवंटन किया जाय।
3. शासनादेश संख्या-619/111(3)/2014-01(नाबार्ड)/2014, दिनांक 27.06.2014 एवं शासनादेश संख्या-797/111(3)/2014-01(नाबार्ड)/2014, दिनांक 02.09.2014 द्वारा स्वीकृत धनराशि पर ही पुनर्आवंटन/समायोजन की कार्यवाही विशेष परिस्थितियों में प्रदान की जा रही है। इसे भविष्य के लिए किसी अन्य कार्य में दृष्टान्त नहीं बनाया जाय।
4. प्रस्तावित पुनर्आवंटन/समायोजन की जाने वाली धनराशि के संबंध में यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त समस्त कार्य नाबार्ड से अनुमोदित हैं एवं वर्तमान में गतिमान हैं।
5. उपरोक्त बिन्दुओं के अतिरिक्त, शासनादेश दिनांक 27.06.2014 एवं दिनांक 02.09.2014, की शेष समस्त शर्तें एवं प्राविधान यथावत लागू रहेंगे।

3. "बुटिपूर्ण" नाम/प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने हेतु दोषी अधिकारियों को एक विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदान किये जाने हेतु दोषी अधिकारियों को चिन्हित करते हुये उनके नाम, पदनाम एवं वर्तमान तैनाती आदि का विवरण शासन को उपलब्ध कराये जाने विषयक शासन के पत्र दिनांक 22.10.2014 एवं तदवश्यक अनुस्मारक दिनांक 11.12.2014 के माध्यम से वांछित आख्या वर्तमान तक शासन में अप्राप्त है। इस संबंध में कृपया तत्काल कार्यवाही अपेक्षित है।

भवदीय
(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या:-20 (1)/III(3)/2014, तददिनांकित।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ऑबरोय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2. अपर मुख्य सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त गढ़वाल/कुमायू मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
4. अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त जिलाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय, राजपुर रोड, देहरादून।
7. समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर-1/2, लो०नि०वि०, उत्तराखण्ड।
8. परियोजना निदेशक, पी०एम०यू०, ए०डी०बी०, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
9. समस्त अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
10. लोक निर्माण अनुभाग-1/2, वित्त अनुभाग-1/2, उत्तराखण्ड शासन।
11. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
अपर सचिव।